



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 51 पटना, बुधवार, 29 अग्रहायण 1939 (श०)
20 दिसम्बर 2017 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डी०ए०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	भाग-9—विज्ञापन
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
भाग-4—बिहार अधिनियम	पूरक
	पूरक-क

6-6

7-10

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं

जल संसाधन विभाग

आवश्यक सूचना

13 दिसम्बर 2017

सं० सिं० को०-1/2001 पार्ट III-571—मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के परिक्षेत्राधीन सिंचाई प्रमंडल, बौसी एवं सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर के अन्तर्गत चन्दन जलाशय योजना के अंतर्गत डैम का सुरक्षात्मक कार्य, सूखनियां वीयर, डकाई वीयर एवं नहर प्रणालियों का पुनर्स्थापन कार्य प्रगति पर है जिससे रब्बी सिंचाई 2017-18 के दौरान चन्दन जलाशय योजना के नहरों में जलापूर्ति बन्द रखने का निर्णय लिया गया है।

अतः संबंधित नहरों के कमांड क्षेत्र के कृषक बन्धुओं से अनुरोध है कि आगामी रब्बी सिंचाई हेतु वैकल्पिक व्यवस्था से पटवन करने का कष्ट करेंगे। उपरोक्त कार्य में आप सबों का सहयोग प्रार्थित है।

आदेश से,

अरूण कुमार द्विवेदी, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचनाएं

13 दिसम्बर 2017

सं० 2/पी०5-20-01/2016 गृ०आ०-9733—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं०-4800 दिनांक 01.04.2016 में निहित प्रावधान के तहत बिहार पुलिस सेवा संवर्ग के निम्नांकित अपर पुलिस अधीक्षकों को आदेश निर्गत की तिथि से स्टाफ ऑफिसर के पद पर वेतनमान-लेवल -13 (पी० बी०-4, ग्रेड वेतन-₹ 8700, अपुनरीक्षित) में औपबधिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	मूल वरीयता क्रमांक
1.	श्री छोटे लाल प्रसाद (अनु० जाति)	06 / 14
2.	श्री आमीर जावेद	28 / 14
3.	श्री अशोक कुमार सिंह	29 / 14
4.	श्री संजय कुमार सिंह	30 / 14
5.	श्री राजीव रंजन-1	31 / 14
6.	श्री राकेश कुमार सिन्हा	32 / 14

2. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ प्रोन्नत पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

3. प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतन का नियतन मौलिक नियमावली के नियम-22 (1) (A) (1) में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा तथा इस संबंध में पदाधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत अपना विकल्प देना होगा।

4. यह प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस०एल०पी० (सी०) सं०-29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दुर्गेश कुमार पाण्डेय, उप-सचिव।

13 दिसम्बर 2017

सं० 7/सी०सी०ए०-1024/2001(खंड-II)गृ०आ०-9731—बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 (7/81) की अध्याय 2 की धारा 12 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, राज्य के सभी जिला दण्डाधिकारियों को उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का अपने जिला के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के एतद् विषयक अधिसूचना संख्या-7566, दिनांक 18.09.2017 के क्रम में अगले तीन महीनों के

लिए अर्थात् दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2018 तक (एक जनवरी दो हजार अठारह से एकतीस मार्च दो हजार अठारह तक) प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करते हैं।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

**कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)**

**अधिसूचना
12 दिसम्बर 2017**

सं० कारा/स्था० (चि०) 01-03/2010-7024—राज्य के कारा निरीक्षणालय (मुख्यालय)/कारा में पदस्थापित निम्नांकित चिकित्सा पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-5 में अंकित स्थल पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नये पद का नाम एवं पदस्थापन का स्थान
1	2	3	4	5
1.	डॉ० परमेश्वर पाण्डेय,	सारण	उप निदेशक, चिकित्सा सेवा कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना।	निदेशक, चिकित्सा सेवा, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना।
2.	डॉ० प्रशांत सिन्हा,	नालन्दा	चिकित्सा पदाधिकारी, शिविर मंडल कारा, फुलवारीशरीफ	उप निदेशक, चिकित्सा सेवा, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना। (अपने वेतनमान में)

2. दोनों पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना प्रभार सौंपकर नव पदस्थापन स्थल पर अविलम्ब योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव—सह—निदेशक (प्र०)।

स्वास्थ्य विभाग

**अधिसूचनाएं
12 दिसम्बर 2017**

सं० 16/आई.जी.1-09/2014(पार्ट)—1378 (आ०चि०)/स्वा०—राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत अधिसूचना संख्या 1283(आ०चि०) दिनांक 20.11.2017 द्वारा राज्य आयुष सोसाइटी, बिहार, पटना का गठन किया गया है। श्री सच्चिदानन्द चौधरी, विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को राज्य आयुष सोसाइटी, बिहार, पटना का सदस्य सचिव—सह—कार्यपालक निदेशक एवं श्री नागेन्द्र प्रसाद, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को राज्य आयुष सोसाइटी, बिहार, पटना का सदस्य—सह—नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है।

2. माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
सच्चिदानन्द चौधरी, विशेष सचिव।

12 दिसम्बर 2017

सं० 16/आई.जी.1-09/2014(पार्ट)—1379 (आ०चि०)/स्वा०—राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत अधिसूचना संख्या 1283(आ०चि०) दिनांक 20.11.2017 द्वारा राज्य आयुष सोसाइटी, बिहार, पटना का गठन किया गया है। श्री प्रशांत कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को राज्य आयुष सोसाइटी, बिहार, पटना के प्रशासी—सह—बजट पदाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

2. माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
सच्चिदानन्द चौधरी, विशेष सचिव।

24 अक्टूबर 2017

सं० 15/ख०-15-02/17-944 (15)/स्वा०,—औषधि एवं अंगराग अधिनियम 1940 की धारा क्रमशः 20, 33F द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औषधि एवं अंगराग नियमावली, 1945 में विहित अनुसूची सी को छोड़कर एवं अनुसूची सी (1) के आइटम नं० 1 से 8 एवं 10, 11 को छोड़कर सभी प्रकार की औषधियाँ, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों की जाँच/विश्लेषण हेतु श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह, संविदा के आधार पर नियुक्त फार्मासिस्ट, बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना-7 को उनके अपने ही मानदेय में बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला के रिक्त सरकारी विश्लेषक के पद पर अगले आदेश तक कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, अवर सचिव।

सं० म०/ योजना - 14/2017—1660
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (मत्स्य)

प्रेषक,

डा० एन विजयलक्ष्मी, भा०प्र०से०,
सचिव,

सेवा में,

प्रमंडलीय आयुक्त, सभी।
जिला पदाधिकारी, सभी।
उप विकास आयुक्त, सभी।

मत्स्य/पटना, दिनांक 12 दिसम्बर 2017

विषय : मत्स्य प्रक्षेत्र के स्वीकृत योजनान्तर्गत योग्य मत्स्यपालकों द्वारा किये जानेवाले निर्माण कार्यों पर 15 जून से 15 अक्टूबर के बीच लोक निर्माण विभाग के स्थगन आदेश को शिथिल करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मत्स्य प्रक्षेत्र से संबंधित योजनाओं के प्रगति की समीक्षा के क्रम में जिला मत्स्य पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि मानसून होने के कारण 15 जून से 15 अक्टूबर के बीच होनेवाले निर्माण कार्यों पर लोक निर्माण विभाग के स्थगन आदेश रहने के कारण मत्स्य विकास योजनाओं का कार्यान्वयन उक्त अवधि में नहीं हो पाता है, जिसके कारण मत्स्य विकास से संबंधित योजनाओं में आशातित प्रगति का आभाव है। वस्तुतः मत्स्य प्रक्षेत्र के स्वीकृत योजनाओं में योग्य लाभूकों द्वारा अनुदानित मुल्य पर स्वलागत अथवा वित्तीय संस्थाओं से वित्त पोषण द्वारा विभागीय मापदंड के अनुरूप निर्माण कार्य स्वयं किया जाता है। उक्त अवधि में लोक निर्माण विभाग के द्वारा निर्माण कार्यों पर स्थगन आदेश के कारण निर्माण हेतु अनुकूल परिस्थिति रहने के बावजूद निर्माण कार्य अवरूद्ध हो जाता है, जिसके कारण कृषि रोडमैप के अनुसार लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। अतः लोक निर्माण विभाग के द्वारा निर्गत स्थगन आदेश को मत्स्य प्रक्षेत्र के योजनाओं के कार्यान्वयन में शिथिल करने की आवश्यकता है।

सम्यक् विचारोपरांत यह निदेश दिया जाता है कि परिक्षेत्र स्तर पर उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति स्थल की जाँच कर साक्ष्य के साथ उक्त अवधि में कार्य कराने के लिए निर्णय लेगी एवं कार्यादेश निर्गत कर सकेगी। साथ ही किये गये कार्य की मापी कर निर्धारित प्रक्रियानुसार लाभूकों को अनुदान भी निर्गत करेगी। संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी कार्यों की प्रगति से जिला स्तरीय कृषि टास्कफोर्स की बैठक में जिला पदाधिकारी को अवगत करायेंगे।

विश्वासभाजन,
डा० एन विजयलक्ष्मी, सचिव।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
(गव्य विकास)

अधिसूचना

8 दिसम्बर 2017

सं० 1821—जिला भभुआ (कैमूर), सासाराम (रोहतास), मोतिहारी (पू० चम्पारण), बेतिया (प० चम्पारण), मुजफ्फरपुर, शिवहर,

समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, जहानाबाद, गया, भागलपुर, खगड़िया, बेगुसराय, हाजीपुर (वैशाली), आरा (भोजपुर) एवं बक्सर में गव्य

विकास निदेशालय, बिहार, पटना के अधीन जिला गव्य विकास कार्यालय स्वीकृत नहीं होने के फलस्वरूप गव्य विकास संबंधी कार्यों के सफल क्रियान्वयन हेतु उक्त जिला के जिला पशुपालन पदाधिकारी को अगले आदेश तक कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

2. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

3. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश्वर पाण्डेय, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 40—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि

सूचना

No. 1567—I, No. 614244F , Rank Ex-Seargent, Name- Lal Mani Rai, S/O Late Marai Rai, Permanent Address – Vill – Fatehpur, PO – Anjani (Parsa), PS- Parsa, Dist – Chapra- Saran, Bihar, Declare that in my service record name of my wife is wrongly recorded as Hemwanti Devi Correct name of my wife is Hema Devi, Affidavit No. 18546/Dated 09:10:2017.

Lal Mani Rai.

सं० 1568—मैं विभांशु, पिता-चन्द्र भूषण प्रसाद, माता-विभा कुमारी, पता-सदल्लीचक, पोस्ट-मित्तनचक, थाना-गोपालपुर, पटना-804453, हालमोकाम-पश्चिमी रामकृष्णनगर, पोस्ट-न्यूजगनपुरा, थाना-रामकृष्णनगर, जिला-पटना-800027 बिहार, घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र संख्या-16761, दिनांक 17.11.2017 से मैं अब विभांशु चन्द्रा के नाम से जाना जाऊंगा।

विभांशु.

No. 1568—1, Bibhanshu S/O- Chandra Bhushan Prasad, R/O- Sadallichak, P.O. Mittan Chak, P.S- Gopalpur, District Patna, A/P-West Ramkrishna Nagar, P.O-New Jaganpura, P.S.- Ramkrishna Nagar, District Patna-800027 declare vide Affd. No. 16761 Dated 17/11/17 that now on wards I shall be known as Bibhanshu Chandra.

Bibhanshu

सं० 1575—मैं, विशेश्वर नाथ, पिता-देवकान्त सिंह, पता-तारेगना गोला, मसौढ़ी, पटना का निवासी हूँ शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ कि मैं दिनांक 30.10.2017 शपथ पत्र सं.-10957 से विशेश्वर नाथ सिंह के नाम से जाना एवं पहचाना जाऊंगा।

विशेश्वर नाथ.

No. 1575—I, VISHESHWAR NATH S/O Deokant Singh born on 10/02/1990 residing at Taregna Gola, P/O + P/S- Masaurhi, Dist –Patna, Bihar, have changed my name to Visheshwar Nath Singh vide affidavit no: 10957 dated 30/10/2017 at Masaurhi (Patna).

VISHESHWAR NATH.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 40—571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 कारा/नि0को0(मुक)—09—28/2017—7006

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय

गृह विभाग (कारा)

संकल्प

11 दिसम्बर 2017

श्री प्रेम कुमार, काराधीक्षक (सम्प्रति सेवा से बर्खास्त) को उनके मंडल कारा, सीतामढ़ी में पदस्थापन के दौरान आपूरक श्री राम लखन यादव से 1,00,000/- (एक लाख) रूपया रिश्वत लेते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिनांक 06.11.2006 को रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इस संदर्भ में श्री कुमार के विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या 73/06 दिनांक 07.11.2006 धारा-07/13 (2) सह पठित धारा-13 (1) (डी0) भ्र0नि0अधी0 1988 दर्ज की गई है।

2. श्री कुमार को न्यायिक हिरासत में लिये जाने के फलस्वरूप उनके गिरफ्तार होने की तिथि 06.11.2006 के अपराहन् से गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक 15799 दिनांक 20.11.2006 द्वारा निलंबित किया गया था।

3. माननीय न्यायालय द्वारा उन्हें जमानत दिये जाने के फलस्वरूप गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना संख्या 1168 दिनांक 31.01.2008 द्वारा उनके योगदान की तिथि 30.11.2007 से निलंबन से मुक्त करते हुए उनका योगदान स्वीकृत किया गया।

4. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (ग) सहपठित 9 (3) (ii) के आलोक में श्री कुमार को पुनः गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना संख्या 1353 दिनांक 06.02.2008 द्वारा निलंबित किया गया। उनके विरुद्ध गठित आरोप पत्र के आधार पर गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना संख्या 11454 दिनांक 02.12.2008 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई।

5. माननीय उच्च न्यायालय, पटना में श्री प्रेम कुमार द्वारा दायर सी0डब्लू0जे0सी0 सं0—17803/2008 प्रेम कुमार बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 04.03.2009 को पारित आदेश के आलोक में गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना सं0—5315 दिनांक 20.07.2009 के द्वारा न्यायादेश की तिथि से निलंबन मुक्त किया गया तथा पुनः उन्हें विभागीय संकल्प ज्ञापांक—672 दिनांक 05.02.2014 के द्वारा निलंबित कर दिया गया।

6. श्री कुमार के विरुद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही हेतु नियुक्त संचालन पदाधिकारी, श्री सुधीर कुमार, प्रधान सचिव—सह—अपर विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें दोनों आरोपों को प्रमाणित पाया गया। तत्पश्चात् सभी विहित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए तथा समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों को अत्यंत गंभीर मानते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार को सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड देने का निर्णय लिया गया।

7. सरकार द्वारा दिये गये वृहत दण्ड पर परामर्श के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(7) के तहत विभागीय पत्रांक—1695 दिनांक 16.03.2015 के द्वारा सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया। तदालोक में सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक—1291 दिनांक 11.08.2015 के द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध उक्त दण्ड के प्रस्ताव पर सहमति दी गई।

8. तत्पश्चात् विभागीय संकल्प ज्ञापांक-6348 दिनांक 14.10.2015 के द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित किया गया। उक्त दण्डादेश के विरुद्ध श्री कुमार के द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया। जिसे अस्वीकृत करते हुए विभागीय पत्रांक-2608 दिनांक 03.05.2016 के द्वारा श्री कुमार को सूचित किया गया।

9. उक्त दण्डादेश एवं पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की अस्वीकृति के विरुद्ध श्री कुमार के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-10664/2016, प्रेम कुमार बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 19.04.2017 को माननीय न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णय पारित किया गया जिसमें “ सेवा से बर्खास्तगी ” आदेश को रद्द करते हुए सभी परिणामी लाभ देने का आदेश दिया गया है।

10. न्यायनिर्णय का operative part निम्नवत है :-

In the uncontested circumstances discussed above, it is manifest that the enquiry report at Annexure-11/1 and its affirmation by the disciplinary authority vide Annexure-13 are a mechanical exercise for none of them have bothered to satisfy themselves whether there is any supporting evidence of giving bribe and its acceptance by the petitioner. Apart from the gross infirmity listed above, the admission by the disciplinary authority that of the papers demanded by the petitioner to prepare his reply, he was not entitled to any other paper other than the vigilance report, is another glaring infirmity in the proceeding.

Last but not the least is the non speaking character of the order of punishment which neither deals with the evidence lending support to the charge not deals with the explanation given by the petitioner. An extreme penalty of dismissal is passed in a routine and mechanical manner dehors the obligation cast on the disciplinary authority under the rules as well as in the judgments on the issue.

For the reason aforementioned, the order of punishment is held resting on no evidence and consequentially Annexure-13 bearing Memo No. 6348 dated 14.10.2015 and Annexure-15 bearing letter No. 2608 dated 03.05.2016 are quashed and set aside. The writ petition is allowed with consequential benefits.

11. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6348 दिनांक 14.10.2015 को निरस्त करते हुए श्री प्रेम कुमार तत्कालीन काराधीक्षक (सम्प्रति सेवा से बर्खास्त) को सेवा में पुनर्स्थापित किया जाता है। उनके निलंबन अवधि एवं सेवा से बर्खास्त रहने की अवधि को कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि माना जायेगा। आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)।

सं0 कारा/नि0को0(उपा0)-02-10/2014-7062

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

संकल्प

13 दिसम्बर 2017

श्री सीप्रियन टोप्पो, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी (सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, जमुई) के विरुद्ध उनके मंडल कारा, मधुबनी में पदस्थापन काल में तत्कालीन उपाधीक्षक से आपसी सामन्जस्य नहीं बनाने, जेनरेटर रहते हुए भी उसे मरम्मत नहीं कराने, कारा जैसे संवेदनशील स्थान पर बिजली विभाग से निदान हेतु ठोस कार्रवाई नहीं किये जाने, नियमित रूप से बैटरी की आपूर्ति नहीं किये जाने, किरासन तेल का उठाव नहीं किये जाने तथा बंदियों का पारिश्रमिक का भुगतान ससमय नहीं किये जाने के प्रतिवेदित आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3779 दिनांक 23.06.2016 द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संयुक्त विभागीय जाँच आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. आयुक्त कार्यालय, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के पत्रांक 25 दिनांक 14.01.2017 से प्राप्त संयुक्त आयुक्त (विभागीय जाँच)-सह-संचालन पदाधिकारी, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के जाँच प्रतिवेदन में श्री टोप्पो के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में गठित छः (06) आरोपों में से आरोप संख्या-01 को पूर्णतः प्रमाणित नहीं पाया गया जबकि शेष पाँच (05) आरोपों को अप्रमाणित पाया गया है। समीक्षोपरान्त पाया गया कि संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर आरोपों की जाँच गहराई से नहीं की गई तथा विषयवस्तु की संवेदनशीलता को देखते हुए सूक्ष्मता से इसकी समीक्षा नहीं की गई। तदालोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम

18 (3) के प्रावधानों के तहत विभागीय ज्ञापांक 3312 दिनांक 27.06.2017 द्वारा संचालन पदाधिकारी के अधिगम से कतिपय बिन्दुओं पर असहमत होते हुए जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री टोप्पो से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

3. श्री टोप्पो के द्वारा अपने पत्रांक 1497/जेल दिनांक 03.08.2017 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जबाब समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि उक्त कारा के पत्रांक-512 दिनांक-25.03.2014, पत्रांक-571 दिनांक-04.04.2014 एवं पत्रांक-644 दिनांक-17.04.2014 द्वारा एवं पुनः व्यक्तिगत रूप से भी कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, मधुबनी से अनुरोध किया गया था। जेनरेटर खराब रहने के संबंध में उनका कहना है कि मरम्मत ठीक से नहीं हो सकी, परन्तु मरम्मत के लिए प्रयास किया गया है। कक्षपालों को ससमय बैट्री उपलब्ध नहीं कराये जाने के आरोप के संबंध में आरोपित का कहना है कि यह आरोप बिल्कुल ही मनगढ़ंत है। जांच समिति को भी ऐसी शिकायत नहीं मिली। आरोपित का कहना है कि किसी ओर से किरासन तेल की कमी की शिकायत नहीं है। माह जून 2014 एवं जुलाई 2014 में दिनांक 21.06.2014 और 17.07.2014 को किरासन तेल का उठाव किया गया है। बंदियों को पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में आरोपित का कहना है कि बंदी पारिश्रमिक के भुगतान हेतु जब भी शाखा प्रभारी द्वारा विपत्र प्रस्तुत किया गया है, उनके द्वारा कार्रवाई की गई है। उपाधीक्षक, जो गोदाम प्रभारी थे, को गैस चुल्हा की खराबी की सूचना होने पर उन्होंने तुरन्त ठीक करवाने के लिए आदेश दिया है। गैस चुल्हा की मरम्मत चालान सं०-102 दिनांक 22.03.2014 एवं चालान सं०-102 दिनांक 15.04.2014 द्वारा करायी गई है।

4. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन, संचिका में उपलब्ध अभिलेख एवं श्री टोप्पो द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा जबाब की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी समीक्षा में पाया गया कि श्री टोप्पो का यह कहना कि कारा में विद्युत आपूर्ति के लिए उनके द्वारा कार्यपालक अभियन्ता से कई बार पत्राचार किया गया एवं व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क किया गया, उनका आरोप से बचने मात्र का प्रयास है। आरोपित का कारा के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी होने के कारण यह दायित्व था कि वे कारा जैसे संवेदनशील स्थान पर सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से कारा में प्रकाश की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करते, परन्तु इसमें वे पूर्णतः विफल रहे हैं। जेनरेटर की मरम्मत भी ससमय नहीं की गई। कक्षपालों को ससमय बैट्री उपलब्ध नहीं कराने एवं बंदियों के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करने के संबंध में उनका जवाब संतोषप्रद नहीं है। इसके अतिरिक्त कारा में जब बिजली की समस्या विद्यमान थी तब उनके द्वारा किरासन तेल का ससमय उठाव नहीं किया जाना उनकी कारा के सुरक्षा के प्रति लापरवाही परिलक्षित करता है। अतः आरोपित पदाधिकारी का द्वितीय कारण पृच्छा का जबाब अस्वीकार्य है।

5. वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री सीप्रियन टोप्पो, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी (सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, जमुई) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14 के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है :-

(i) निंदन।

(ii) दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने का दंड।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

सं० कारा/नि०को०(उपा०)-02-10/2014-7063

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

संकल्प

13 दिसम्बर 2017

श्री सुरेश चौधरी, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन उपाधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी (सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, सुपौल) के विरुद्ध उनके मंडल कारा, मधुबनी में पदस्थापन काल में तत्कालीन अधीक्षक से आपसी सामन्तस्य नहीं बनाने, जेनरेटर रहते हुए भी उसे मरम्मत नहीं कराने, कारा जैसे संवेदनशील स्थान पर बिजली विभाग से निदान हेतु ठोस कार्रवाई नहीं किये जाने, नियमित रूप से बैट्री की आपूर्ति नहीं किये जाने, किरासन तेल का उठाव नहीं किये जाने तथा बंदियों का पारिश्रमिक का भुगतान ससमय नहीं किये जाने के प्रतिवेदित आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3778 दिनांक 23.06.2016 द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संयुक्त विभागीय जाँच आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. आयुक्त कार्यालय, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के पत्रांक 26 दिनांक 14.01.2017 से प्राप्त संयुक्त आयुक्त (विभागीय जाँच)-सह-संचालन पदाधिकारी, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के जाँच प्रतिवेदन में श्री चौधरी के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में गठित छः (06) आरोपों में से किसी भी आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया। समीक्षोपरान्त पाया गया कि संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर आरोपों की जाँच गहराई से नहीं की गई तथा विषयवस्तु की संवेदनशीलता को देखते हुए सूक्ष्मता से इसकी समीक्षा नहीं की गई। तद्आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 18 (3) के प्रावधानों के तहत विभागीय ज्ञापांक 3311 दिनांक

27.06.2017 द्वारा संचालन पदाधिकारी के अधिगम से कतिपय बिन्दुओं पर असहमत होते हुए जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री चौधरी से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

3. श्री चौधरी के द्वारा अपने पत्रांक 1097 दिनांक 26.07.2017 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि मंडल कारा, मधुबनी में विद्युत आपूर्ति की स्थिति एवं उसके निराकरण की समस्या इतनी गंभीर थी, कि यह न तो उपाधीक्षक और न ही कारा अधीक्षक के वश में थी, और उसको सुव्यवस्थित किये जाने का अनुश्रवण सीधे महानिरीक्षक के स्तर से किया जा रहा था। जेनरेटर खराब रहने एवं बनवाने के संबंध में आरोपित का कहना है कि कारा में लगे जेनरेटर 7.5 के0वी0ए0 काफी पुराना हो चुका है और उसे चलाने के ऑपरेटर की नियुक्ति नहीं की गई है। फिर भी उनके द्वारा एन-केन-प्रकारेण से किसी तरह उसी पुराने जेनरेटर को चलवाया जाता था एवं प्रकाश की व्यवस्था की गई थी। जवाब के अनुसार उनके द्वारा अधीक्षक से तालमेल स्थापित रखने में कभी कोई कमी नहीं की गई है। कक्षपालों को ससमय बैट्री नहीं दिये जाने के संबंध में कहना है कि प्रत्येक माह टार्च का बैट्री मँगाया जाता था तथा कारा कर्मियों में वितरण कर दिया जाता था। किरासन तेल उठाव के संबंध में उनका कहना है कि किरासन तेल का उठाव प्रत्येक माह नियमित रूप से जन वितरण प्रणाली के दुकान से किया जाता था। बंदी पारिश्रमिक के बिन्दु के संबंध में उनका कहना है कि बंदी पारिश्रमिक का भुगतान बंदी पारिश्रमिक पंजी के माध्यम से किया जाता है एवं बंदी पारिश्रमिक पंजी से स्पष्ट होता है कि बंदी पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है एवं इसे अधीक्षक द्वारा सत्यापित भी किया गया है।

4. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन, संचिका में उपलब्ध अभिलेख एवं श्री चौधरी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा जवाब की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी समीक्षा में पाया गया कि श्री चौधरी का यह कहना कि कारा में विद्युत की समस्या इतनी गंभीर थी कि उसका निराकरण उपाधीक्षक और काराधीक्षक के वश में नहीं थी, उनकी कर्तव्यहीनता एवं गैर जिम्मेदार होने का द्योतक है। उपाधीक्षक का कारा के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में यह दायित्व था कि वे कारा में बिजली की समस्या के मद्देनजर सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से प्रकाश की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कराते। कारा में अधिष्ठापित जेनरेटर का चालू अवस्था में नहीं रहना, मरम्मत के तुरंत बाद खराब हो जाना उनकी लापरवाही को इंगित करता है। संयुक्त जांच दल के जांच में पाया गया कि कारा में विद्युत समस्या के बावजूद कक्षपालों को ससमय बैट्री नहीं उपलब्ध कराया जाता था और न ही समय पर किरासन तेल का उठाव किया जाता था। बंदियों का पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जा रहा था। उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि इनका अधीक्षक से आपसी सामन्जस्य एवं ताल-मेल में कमी थी। अतएव आरोपित का द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब अस्वीकार्य है।

5. वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री सुरेश चौधरी, तत्कालीन उपाधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी (सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, सुपौल) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14 के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है :-

(i) निंदन।

(ii) दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दंड।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 40-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>